



# दैनिक समाचार पत्र

# भारतार्थ खबर

## खबर नहीं, उसका अर्थ

देश | समाज | राजनीति | अर्थव्यवस्था | शिक्षा | संस्कृति | दुनिया



## 25 साल की जनसेवा पर पीएम मोदी ने आडवाणी से लिया आशीर्वाद, बोले- उनका योगदान अमिट



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी

के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आडवाणी का आशीर्वाद लिया और उनके दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन तथा राष्ट्र के प्रति योगदान

को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा करते हुए कहा कि उन्होंने आडवाणी जी से उनके आवास पर मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने आडवाणी के दशकों की जनसेवा और राष्ट्रीय जीवन में योगदान को देश पर अमिट छाप छोड़ने वाला बताया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की प्रगति को मजबूत करने में आडवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 7 अक्टूबर 2001 से शुरू हुआ प्रशासनिक सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर संवैधानिक पद पर अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में करीब 13 वर्ष कार्य किया और मई 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद

उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह 7 अक्टूबर 2026 को उनके सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर देशभर में भाजपा की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पार्टी ने प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने को 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत रेखांकित किया। विभिन्न राज्यों में 'विकसित भारत संकल्प सभा' और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। आडवाणी का राजनीतिक सफर भी अहम लालकृष्ण आडवाणी भारतीय राजनीति में भाजपा के प्रमुख नेताओं में रहे हैं। उन्होंने केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और 2002 से 2004 तक उपप्रधानमंत्री भी रहे। भाजपा के संगठनात्मक विस्तार और राष्ट्रीय

राजनीति में पार्टी की भूमिका मजबूत करने में उनका लंबा राजनीतिक योगदान रहा है। प्रधानमंत्री और आडवाणी की यह मुलाकात ऐसे अवसर पर हुई, जब मोदी अपने प्रशासनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर देशभर में आयोजित कार्यक्रमों के केंद्र में रहे। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री का संदेश उनके राजनीतिक जीवन में आडवाणी के योगदान और वरिष्ठ नेता के प्रति सम्मान को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री की इस मुलाकात को उनके 25 वर्ष के प्रशासनिक सफर के अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता से आशीर्वाद लेने के रूप में देखा गया। वहीं, आडवाणी के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका का उल्लेख प्रधानमंत्री के संदेश में प्रमुखता से हुआ।

## पीएम मोदी ने वायु योद्धाओं को किया नमन, बोले 'भारत को अपने एयर वॉरियर्स पर गर्व'

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2026। भारतीय वायु सेना के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र



मोदी ने देश के वायु योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भारतीय वायु सेना की वीरता, समर्पण और देश के आकाश की सुरक्षा में निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने संदेश में कहा कि भारत को अपने एयर वॉरियर्स पर गर्व है। उन्होंने वायु सेना दिवस

के अवसर पर देश के आसमान की रक्षा करने वाले वायु योद्धाओं के साहस और प्रतिबद्धता को सलाम किया। 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी स्थापना भारतीय वायु सेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में भारतीय वायु सेना अपनी स्थापना के 94 वर्ष पूरे कर रही है। एक

छोटे से शुरुआती बेड़े से सफर शुरू करने वाली भारतीय वायु सेना आज आधुनिक लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों से सुसज्जित एक महत्वपूर्ण सामरिक शक्ति बन चुकी है। 'अचूक, अमेघ और सटीक' पर केंद्रित समारोह वायु सेना दिवस 2026 की थीम 'इंडियन एयर फोर्स इनफ्लेबल, इम्पेनेट्रेबल

एंड प्रिसाइज', अर्थात 'भारतीय वायु सेना अचूक, अमेघ और सटीक' रखी गई है। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने भी अपने संदेश में देश की संप्रभुता और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वायु सेना की सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना अपनी युद्धक तैयारी को लगातार परख रही है और नई तकनीकों को तेजी से संचालन में शामिल कर रही है। विभिन्न सैन्य अभ्यासों और तकनीकी पहलों के माध्यम से बल की परिचालन क्षमता को मजबूत किया जा रहा है। वायु सेना दिवस देश के उन सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश की हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। प्रधानमंत्री का संदेश इसी राष्ट्रीय भावना को रेखांकित करता है कि भारतीय वायु योद्धाओं का साहस, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा देश की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है।

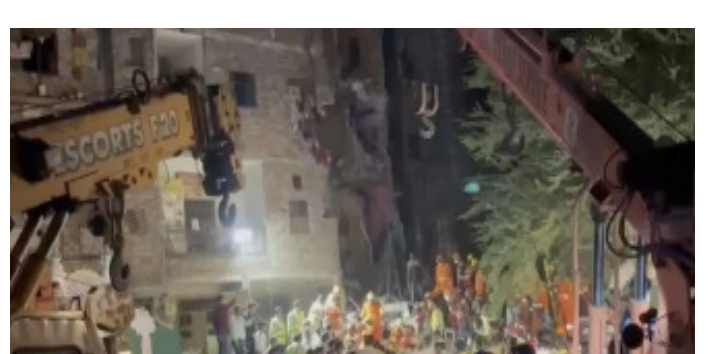
## एयर इंडिया की AI2414 में तकनीकी खराबी, दिल्ली पहुंचने के बाद यात्रियों को एक घंटे से अधिक इंतजार

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2026। बेंगलुरु से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की उड़ान AI2414 गुरुवार सुबह निर्धारित समय से करीब 25 मिनट पहले दिल्ली पहुंच गई, लेकिन लैंडिंग के बाद तकनीकी समस्या के कारण यात्रियों को काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, विमान के दिल्ली एयरपोर्ट के मुख्य रनवे को पार करने के दौरान तकनीकी खराबी सामने आई। इसके चलते विमान अपने निर्धारित स्टॉप तक समय पर नहीं पहुंच सका और यात्रियों को एक घंटे से अधिक समय तक विमान में इंतजार करना पड़ा। बताया गया कि उड़ान को दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर उतरना था, लेकिन परिस्थितियों के कारण विमान टर्मिनल-2 पर लैंड हुआ। इसके बाद यात्रियों को बसों के माध्यम से टर्मिनल-3 तक पहुंचाया गया। तकनीकी स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर विमान में आई खराबी को ठीक किया। तकनीकी समस्या दूर होने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली और उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए टर्मिनल-3 ले जाया गया। घटना के कारण यात्रियों को असुविधा जरूर हुई, हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार तकनीकी टीम की ओर से समस्या का समाधान किए जाने के बाद स्थिति सामान्य हो गई। विमान संचालन में तकनीकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण ऐसी परिस्थितियों में अतिरिक्त समय लगना संभव है।

## सीमापुरी में भरभराकर गिरी बहुमंजिला इमारत, चार की मौत मलबे से 11 लोग निकाले गए

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2026। राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी हिस्से सीमापुरी में बुधवार को एक बहुमंजिला आवासीय इमारत अचानक ढहने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में दो बच्चों और करीब चार माह की गर्भवती महिला समेत कम से कम तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, जबकि आठ लोग घायल हुए। गुरुवार सुबह मलबे से एक और शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गई। राहत और बचाव दल लगातार मलबा हटाकर संभावित रूप से फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। हादसा बुधवार दोपहर करीब 3:15 से 3:30 बजे के बीच न्यू सीमापुरी के ईदगाह-मछली मंडी के पास घनी

आबादी वाले इलाके में हुआ। इमारत के अचानक गिरते ही आसपास अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दिल्ली दमकल सेवा,



दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और नगर निगम की टीमों मौके पर पहुंचीं। संकरी

गलियों के कारण भारी मशीनरी पहुंचाने में बचावकर्मियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मलबे से निकाले गए लोग,

लिए राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, ताहिहपुर ले जाया गया। घायलों में तीन वर्षीय बच्चा भी शामिल है। बचाव अभियान के दौरान खोजी कुत्तों और भारी मशीनों की भी मदद ली गई। मृतकों में करीब 12 वर्षीय एक बच्ची, करीब डेढ़ वर्ष का एक बच्चा और 21 वर्षीय गुलफसा शामिल हैं, जो लगभग चार माह की गर्भवती थीं। चौथे शव की बरामदगी के बाद मृतक संख्या चार हो गई है। अधिकारियों ने मृतकों की पहचान और घटना की परिस्थितियों की पुष्टि के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। इमारत की उम्र और निर्माण को लेकर जांच नगर निगम के अनुसार, यह ढांचा करीब 20 से 25 वर्ष पुराना था और दिल्ली शहरी

आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) के भूखंड पर स्थित था। स्थानीय लोगों के अनुसार, इमारत में समय के साथ अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण किया गया था। इन दावों की आधिकारिक जांच की जा रही है। इमारत गिरने के कारण को लेकर भी अभी अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि मंगलवार रात महसूस किए गए भूकंपीय झटकों के बाद इमारत में दरारें आ गई थीं। वहीं, ने मृतकों की पहचान और घटना की परिस्थितियों की पुष्टि के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। इमारत की उम्र और निर्माण को लेकर जांच नगर निगम के अनुसार, यह ढांचा करीब 20 से 25 वर्ष पुराना था और दिल्ली शहरी

प्रभावित इमारत के ढहने से आसपास के दो भवन भी प्रभावित हुए तथा पास स्थित ईदगाह की दीवार को भी नुकसान पहुंचा। बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। घनी आबादी और संकरी गलियों के बीच राहत कार्य को सुरक्षित ढंग से आगे बढ़ाना बचाव दल के लिए चुनौती बना रहा। फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान मलबे की जांच, संभावित रूप से फंसे लोगों की तलाश और घायलों के उपचार पर है। हादसे की परिस्थितियों तथा इमारत की संरचनात्मक स्थिति की विस्तृत जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर बहुमंजिला ढांचा अचानक क्यों भरभराकर गिरा।

## ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दूसरे दिन भी सड़क पर उतरी कांग्रेस, राहुल-प्रियंका समेत विपक्षी नेता हिरासत में

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2026। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस तथा विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा समेत कई विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली तथा मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठाए।



लोकतंत्र के लिए 'काला दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की है। जंतर-मंतर की ओर बढ़ने की कोशिश बुधवार को विपक्षी सांसदों ने जंतर-मंतर की ओर मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की

थी। करीब 200 सांसदों के प्रदर्शन में शामिल होने की बात सामने आई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी वाड़ा सड़क पर बैठीं और बाद में पुलिस कार्रवाई के बीच संविधान की प्रति हाथ में लिए नजर आईं। प्रदर्शन की तस्वीरों में राहुल गांधी भी उनके साथ दिखाई दिए। इन दृश्यों की तस्वीरें और वीडियो कांग्रेस तथा

समाचार माध्यमों के जरिए सामने आए। SIR और मतदाता सूची पर कांग्रेस के सवाल कांग्रेस और उसके सहयोगी विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हो सकते हैं। विपक्ष ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। राहुल गांधी ने भी प्रदर्शन के दौरान इस मांग को दोहराया। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग और भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। आयोग का पक्ष है कि मतदाता सूची की समीक्षा का उद्देश्य अपात्र, डुप्लीकेट या अन्य अयोग्य प्रविष्टियों को हटाना और मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाना है। इसलिए SIR को लेकर राजनीतिक दलों के आरोपों और निर्वाचन आयोग

के आधिकारिक पक्ष को अलग-अलग संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है। गुरुवार को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कांग्रेस ने बुधवार के घटनाक्रम के बाद 8 अक्टूबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। पार्टी के अनुसार, यह प्रदर्शन CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उसकी मांगों, SIR और मतदाता सूची से जुड़े सवालों को लेकर होगा। दिल्ली में विपक्षी दलों का आंदोलन जारी रहने के संकेत भी सामने आए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि कांग्रेस और विपक्षी दल अपने आंदोलन को किस रूप में आगे बढ़ाते हैं तथा निर्वाचन आयोग इन सवालों पर क्या आधिकारिक स्पष्टीकरण देता है।

## जानलेवा हमले के बाद फिर अपने पैरों पर खड़े हुए 'हीरो' पायलट स्मित मच्छार, अस्पताल में चले 10 कदम

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2026। पलाईडुबई की उड़ान के कॉकपिट में जानलेवा हमले का सामना करने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। गंभीर चोटों और खोपड़ी की सर्जरी के बाद अब उन्होंने अस्पताल में अपने पैरों पर खड़े होकर करीब 10 कदम चलने में सफलता हासिल की है। परिवार के एक सदस्य ने यह जानकारी दी है। कैप्टन मच्छार 30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही पलाईडुबई की उड़ान FZ1073 में ज़ख्मी पर थे। उड़ान के दौरान उनके ओमानो-को-पायलट ने कथित तौर पर कॉकपिट में क्रैश एक्स से उन पर हमला कर दिया था। हमले में कैप्टन मच्छार को गंभीर चोटें आईं और उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ।

इसके बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफलता हासिल की, जिससे अन्य क्रू सदस्य और यात्रियों को अंदर पहुंचकर स्थिति



संभालने का मौका मिला। घटना के बाद विमान ने आपात स्थिति में सऊदी अरब के तबुक में लैंडिंग की। कैप्टन मच्छार को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी आपात सर्जरी की गई। रिपोर्टों के अनुसार, चिकित्सकों ने उनकी क्षतिग्रस्त खोपड़ी का पुनर्निर्माण किया। बाद में उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए संयुक्त अरब अमीरात ले जाया गया। अब परिवार की ओर से सामने आया नया स्वास्थ्य

अपडेट राहत देने वाला है। परिवार के सदस्य के मुताबिक, कैप्टन मच्छार ने अस्पताल में 10 कदम चलकर अपनी रिकवरी की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय मिशन भी उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखे हुए हैं तथा परिवार और चिकित्सकों के संपर्क में हैं। इस घटना में कैप्टन मच्छार की भूमिका को व्यापक स्तर पर साहस और कर्तव्यनिष्ठा के उदाहरण के रूप में देखा गया है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने विमान और उसमें सवार यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। विमान में कुल 174 लोग सवार थे और यात्रियों तथा चालक दल के सदस्यों ने मिलकर हमलावर को काबू करने के बाद विमान को सुरक्षित उतारने में मदद की। कैप्टन मच्छार की हालत में सुधार की यह खबर ऐसे समय आई है, जब विमान में हुई घटना की जांच भी जारी है।

## जीएसटी परिषद की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे डी.के. शिवकुमार, कर्नाटक भवन में हुआ स्वागत

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2026। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एवं राज्य के वित्त मंत्री डी.के. शिवकुमार 8 अक्टूबर को नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कर्नाटक भवन में मीडिया से बातचीत की और इसके बाद 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए रवाना हुए। कर्नाटक भवन में मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा ऐसे समय हुई है जब जीएसटी

की गिरफ्तारी संबंधी शक्तियों में प्रस्तावित बदलाव को लेकर अपनी विंताएं सामने रखी हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश उन राज्यों में बताए गए हैं जिन्होंने कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रवर्तन संबंधी अधिकार बनाए रखने की आवश्यकता जताई है। ऐसे सुधारों पर राज्यों की नजर 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कर प्रशासन और अनुपालन व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के बीच कर्नाटक समेत कई राज्यों ने कर अधिकारियों



सरकार की ओर से जीएसटी व्यवस्था में राज्य के हितों से जुड़े मुद्दे उठाए

जाने की संभावना है। बैठक से पहले संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रावधानों में विशेष छूट सहित कुछ मुद्दों पर राज्य का पक्ष रखने वाले हैं। जीएसटी व्यवस्था का सीधा प्रभाव कारोबार, उपभोक्ताओं, राज्यों के राजस्व और कर अनुपालन पर पड़ता है। इसलिए परिषद में होने वाले निर्णयों का असर केवल सरकारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उद्योग, छोटे कारोबार और आम उपभोक्ताओं तक भी पहुंचता है। मीडिया से संवाद के बाद बैठक के लिए रवाना नई दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में

मुख्यमंत्री ने मीडिया को जानकारी देने के बाद जीएसटी परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रस्थान किया। इससे पहले उन्हें कर्नाटक भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जीएसटी परिषद केंद्र पड़ता है। इसलिए परिषद में होने वाले निर्णयों का असर केवल सरकारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उद्योग, छोटे कारोबार और आम उपभोक्ताओं तक भी पहुंचता है। मीडिया से संवाद के बाद बैठक के लिए रवाना नई दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में

मुख्यमंत्री ने मीडिया को जानकारी देने के बाद जीएसटी परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रस्थान किया। इससे पहले उन्हें कर्नाटक भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जीएसटी परिषद केंद्र पड़ता है। इसलिए परिषद में होने वाले निर्णयों का असर केवल सरकारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उद्योग, छोटे कारोबार और आम उपभोक्ताओं तक भी पहुंचता है। मीडिया से संवाद के बाद बैठक के लिए रवाना नई दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में

का दायित्व भी संभालते हैं, परिषद में राज्य का पक्ष रख रहे हैं। जीएसटी परिषद की आधिकारिक सूची में भी उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री के रूप में दर्ज किया गया है। बैठक में कर प्रशासन को सरल बनाने और कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखने पर विशेष ध्यान रहने की उम्मीद है। राज्यों की ओर से उठाई जा रही विंताओं के बीच परिषद के फैसले आने वाले समय में जीएसटी व्यवस्था की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।

विश्व  • भारत  • राजनीति  • अर्थव्यवस्था  • विश्व  • राष्ट्रिय  • प्रतिष्ठान

बेंगलुरु, शुक्रवार , ०9 अक्टूबर 2026

## सम्पादकीय

**महंगाई की मार और ब्याज दर की दीवार:विकास की रफ्तार कितनी सुरक्षित?**

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com अर्थव्यवस्था के सामने सबसे कठिन सवाल उस समय खड़ा होता है, जब एक साथ दो लक्ष्य साधने पड़ें महंगाई को काबू में रखना और विकास की गति को बनाए रखना। भारतीय रिजर्व बैंक का ताजा फैसला इसी चुनौती का संकेत है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया है। करीब चार वर्ष बाद हुई यह पहली बढ़ोतरी है। साथ ही नीति रुख को “स्यूदल” से बदलकर ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ किया गया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, पश्चिम एशिया का तनाव, कमजोर रुपया और खाद्य कीमतों का दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौती बन रहे हैं। सितंबर में खुदरा महंगाई बढ़कर लगभग 5.40 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि अगस्त में यह 4.82 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा अभी अनुमान पर आधारित है, लेकिन इससे महंगाई के दबाव की दिशा का अंदाजा जरूर मिलता है। ब्याज दर बढ़ाना क्यों जरूरी समझा गया? महंगाई केवल बाजार में बढ़ती कीमतों का नाम नहीं है। लगातार महंगाई बनी रहे तो लोगों की क्रय शक्ति घटती है, बचत वास्तविक मूल्य प्रभावित होता है और कारोबार की लागत बढ़ती है। यदि उपभोक्ताओं और कारोबारियों की महंगाई संबंधी उम्मीदें भी ऊपर जाने लगें तो समस्या और जटिल हो सकती है। आरबीआई के हालिया सर्वेक्षण में भी परिवारों की महंगाई संबंधी उम्मीदों में बढ़ोतरी का संकेत मिला है। ऐसे वातावरण में ब्याज दर बढ़ाना केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध प्रमुख मौद्रिक उपायों में से एक है। महंगे कर्ज से मांग की गति कुछ धीमी हो सकती है, अत्यधिक ऋण-आधारित खर्च पर अंकुश लग सकता है और महंगाई की उम्मीदों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल है यदि महंगाई का बड़ा कारण कच्चा तेल, खाद्य वस्तुएं या युद्ध जैसी आपूर्ति संबंधी समस्याएं हैं, तो केवल ब्याज दर बढ़ाने से उनका उत्पादन या आपूर्ति कैसे बढ़ेगी? यही मौद्रिक नीति की सबसे बड़ी सीमा है। आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? रेपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि कागज पर छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर धीरे-धीरे बैंकिंग व्यवस्था और ऋण बाजार के माध्यम से आम परिवार तक पहुंच सकता है। प्लोटिंग ब्याज दर वाले गृह ऋण, वाहन ऋण और अन्य ऋणों की लागत बढ़ सकती है। नई उधारी लेने वाले परिवारों के लिए ईएमआई का बोझ भी बढ़ सकता है। दूसरी ओर, सावधि जमा और कुछ बचत साधनों पर बेहतर ब्याज मिलने की संभावना बचतकर्ताओं के लिए सकारात्मक पक्ष हो सकती है। यानी ब्याज दर का प्रभाव एकतरफा नहीं होता कर्जदार पर दबाव और बचतकर्ता को संभावित लाभ, दोनों साथ दिखाई दे सकते हैं। फिर भी निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए स्थिति अधिक संवेदनशील है। भोजन, ईंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी आवश्यकताओं के खर्च बढ़ने के बीच यदि कर्ज की लागत भी बढ़े, तो घरेलू बजट पर दोहरा दबाव पड़ सकता है। छोटे कारोबार के लिए चुनौती भारत की अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम कारोबार रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण आधार हैं। इनके लिए बैंक ऋण की लागत बढ़ना केवल वित्तीय समस्या नहीं, बल्कि विस्तार, मशीनरी खरीद, कार्यशील पूंजी और नए रोजगार के निर्णयों को प्रभावित करने वाला कारक हो सकता है। बड़े उद्योग अपेक्षाकृत बेहतर वित्तीय विकल्प तलाश सकते हैं, लेकिन छोटे उद्यमों के पास विकल्प सीमित होते हैं। यदि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो कुछ कारोबार निवेश टाल सकते हैं। इसका असर नई नौकरियों और स्थानीय मांग पर पड़ सकता है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है। अनियंत्रित महंगाई छोटे कारोबार की लागत को भी बढ़ाती है। कच्चा माल, परिवहन, बिजली और मजदूरी महंगी होने पर कारोबारी मार्जिन पर दबाव आता है। इसलिए छोटे कारोबार के लिए केवल कम ब्याज दर ही समाधान नहीं है, स्थिर कीमतें भी उतनी ही जरूरी हैं। क्या विकास की रफ्तार खतरे में है? दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ाने के साथ वित्त वर्ष 2026–27 के लिए आर्थिक विकास का अनुमान बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत किया है। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती को लेकर पूरी तरह निराश नहीं है। यही वह संतुलन है जिसे समझना जरूरी है। ब्याज दर बढ़ोतरी का उद्देश्य विकास रोकना नहीं, बल्कि कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करते हुए दीर्घकालिक विकास के लिए स्थिर वातावरण बनाए रखना है। मगर यदि दरों में लगातार बढ़ोतरी होती है तो निवेश, उपभोग और रोजगार पर उसका संचयी प्रभाव दिखाई दे सकता है। इसलिए असली प्रश्न 25 आधार अंकों की एक बढ़ोतरी से अधिक आगे की नीति का है। आरबीआई गवर्नर ने भी संकेत दिया है ।

## कहीं पानी के लिए तरसता भारत, कहीं बारिश से बेहाल जल नीति कब बदलेगी?

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com भारत में मानसून केवल मौसम की घटना नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, खेती, ग्रामीण रोजगार और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। यही कारण है कि जब देश के एक हिस्से में किसान बारिश के अभाव में खेतों में बुआई नहीं कर पाता और दूसरे हिस्से में कुछ ही घंटों की तेज बारिश जलभराव, फसल नुकसान और जनजीवन में व्यवधान पैदा कर देती है, तो सवाल केवल मौसम का नहीं रह जाता। सवाल यह भी है कि हमारी जल नीति बदलते मौसम की चुनौतियों के अनुरूप कितनी तैयार है। आंध्र प्रदेश की ताजा स्थिति इस विरोधाभास को सामने लाती है। राज्य सरकार ने 2026 के खरीफ मौसम के लिए 21 जिलों के 388 मंडलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इनमें 283 मंडलों को गंभीर और 105 को मध्यम सूखे की श्रेणी में रखा गया है। जून से अगस्त के बीच राज्य में सामान्य 424.3 मिलीमीटर के मुकाबले 197.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, यानी 53.4 प्रतिशत की कमी रही। दूसरी ओर, देश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 8 अक्टूबर को तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश तथा गरज-चमक की चेतावनी दी है। उत्तराखंड सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भारी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है। यह तस्वीर

## जब परीक्षा में छात्र नहीं, एआई भी बैठे:बदलती शिक्षा व्यवस्था की नई चुनौती

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से एक बुनियादी सवाल के इर्द-गिर्द घूमती रही है परीक्षा आखिर किस चीज को मापती है? विद्यार्थी ने कितना याद किया, कितना समझा या किसी समस्या को हल करने की उसकी क्षमता कितनी है? जन्परेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से विस्तार ने इस पुराने सवाल को अब बिल्कुल नई चुनौती दे दी है। जब एआई कुछ ही सेकंड में निबंभ लिख सकता है, गणितिय समस्याओं को समझा सकता है, कोड तैयार कर सकता है और किसी विषय पर विस्तृत उत्तर दे सकता है, तब केवल याददाश्त और लिखने की गति पर आधारित परीक्षा का उद्देश्य फिर से विचार मांगता है। इसी बदलती वास्तविकता की एक दिलचस्प मिसाल बेंगलुरु स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान में सामने आई है। संस्थान के जन्परेटिव एआई पाठ्यक्रम में पारंपरिक पेन-पेपर मध्यावधि परीक्षा के बजाय विद्यार्थियों को अपना चोटबॉट तैयार करने और उससे 15 प्रश्नों के उत्तर दिलाने को कहा गया। विद्यार्थियों को चोटबॉट के लिए निर्देश तैयार करने, पाठ्यक्रम को उसकी उसकी ‘मेमोरी’ में उपलब्ध

## संपादकीय

## भारत, कहीं बारिश से बेहाल जल नीति कब बदलेगी?

रखा जाता है। तेज बारिश के दौरान बड़ी मात्रा में पानी नदियों, नालों और जल निकासी तंत्र से होकर बह जाता है। दूसरी ओर, कुछ महीनों बाद वही क्षेत्र भूजल संकट का सामना कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर बाढ़ के पानी को रोक लेना संभव या उचित है। बाढ़ के अपने पर्यावरणीय और नदीय कारण होते हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर जल संचयन, तालाबों का पुनर्जीवन, छोटे जलाशयों का संरक्षण, खेत-तालाब और भूजल पुनर्भरण जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की गुंजाइश निश्चित रूप से है। यही वह स्थान है जहां में सरकार के सामने तत्काल राहत, फसल नुकसान का आकलन, ऋण पुनर्गठन, बीज-खाद सहायता और किसानों को आर्थिक राहत देने की चुनौती होती है। आंध्र प्रदेश में भी सूखा घोषणा के बाद प्रभावित किसानों के लिए आपात ऋण और राहत उपायों का रास्ता खुला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर वर्ष संकट आने के बाद राहत देना पर्याप्त है? यदि किसी क्षेत्र में लगातार वर्षा की ताल-सुरेखित कृषि व्यवस्था होना चाहिए। सूखा राहत जरूरी है, लेकिन वह स्थायी समाधान नहीं है। भारत में समस्या केवल यह नहीं कि कहीं पानी कम गिर रहा है। समस्या यह भी है कि जब बहुत पानी आता है, तब उसका कितना हिस्सा सुरक्षित

देना स्वाभाविक है। आईआईएम बेंगलुरु का प्रयोग क्या बताता है? इस प्रयोग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विद्यार्थियों को एआई का इस्तेमाल करने की अनुमति पर नहीं दी गई, बल्कि उन्हें एआई प्रणाली तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें यह तय करना पड़ा कि चोटबॉट को किस तरह निर्देश दिए जाएं, कौन-सी सामग्री उपलब्ध कराई जाए और बेहतर उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रणाली को कैसे तैयार किया जाए। अर्थात परीक्षा का केंद्र “सही उत्तर कि याद है या नहीं” से हटकर “समस्या को हल करने के लिए उपलब्ध तकनीक का इस्तेमाल कितनी समझदारी से किया जा सकता है” की ओर चला गया। यह उद्योग जनत की वास्तविक जरूरतों के भी करीब है। कार्यस्थल पर व्यक्ति से हर जानकारी याद रखने की अपेक्षा नहीं होती। उससे अपेक्षा होती है कि वह सही सवाल पूछे, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करे, परिणाम की जांच करे और जिम्मेदारी के साथ निर्णय ले। लेकिन क्या एआई पर पूरी निर्भरता उचित होगी? यहां सावधानी की आवश्यकता भी उतनी ही है। यदि विद्यार्थी हर समस्या का समाधान एआई

से मांगने लगे और स्वयं विचार करने

की क्षमता कमजोर होने लगे, तो शिक्षा का मूल उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। एआई उत्तर दे सकता है, लेकिन वह हमेशा सही उत्तर देगाकू दी गई, बल्कि उन्हें एआई प्रणाली तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें यह तय करना पड़ा कि चोटबॉट को किस तरह निर्देश दिए जाएं, कौन-सी सामग्री उपलब्ध कराई जाए और बेहतर उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रणाली को कैसे तैयार किया जाए। अर्थात परीक्षा का केंद्र “सही उत्तर कि याद है या नहीं” से हटकर “समस्या को हल करने के लिए उपलब्ध तकनीक का इस्तेमाल कितनी समझदारी से किया जा सकता है” की ओर चला गया। यह उद्योग जनत की वास्तविक जरूरतों के भी करीब है। कार्यस्थल पर व्यक्ति से हर जानकारी याद रखने की अपेक्षा नहीं होती। उससे अपेक्षा होती है कि वह सही सवाल पूछे, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करे, परिणाम की जांच करे और जिम्मेदारी के साथ निर्णय ले। लेकिन क्या एआई पर पूरी निर्भरता उचित होगी? यहां सावधानी की आवश्यकता भी उतनी ही है। यदि विद्यार्थी हर समस्या का समाधान एआई

से मांगने लगे और स्वयं विचार करने

अलग-अलग प्रकार की मूल्यांकन पद्धति आवश्यक हो सकती है। कुछ विषयों में बिना एआई के मूलभूत ज्ञान हो सकता है। एआई उत्तर दे सकता है, लेकिन वह हमेशा सही उत्तर देगाकू दी गई, बल्कि उन्हें एआई प्रणाली तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें यह तय करना पड़ा कि चोटबॉट को किस तरह निर्देश दिए जाएं, कौन-सी सामग्री उपलब्ध कराई जाए और बेहतर उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रणाली को कैसे तैयार किया जाए। अर्थात परीक्षा का केंद्र “सही उत्तर कि याद है या नहीं” से हटकर “समस्या को हल करने के लिए उपलब्ध तकनीक का इस्तेमाल कितनी समझदारी से किया जा सकता है” की ओर चला गया। यह उद्योग जनत की वास्तविक जरूरतों के भी करीब है। कार्यस्थल पर व्यक्ति से हर जानकारी याद रखने की अपेक्षा नहीं होती। उससे अपेक्षा होती है कि वह सही सवाल पूछे, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करे, परिणाम की जांच करे और जिम्मेदारी के साथ निर्णय ले। लेकिन क्या एआई पर पूरी निर्भरता उचित होगी? यहां सावधानी की आवश्यकता भी उतनी ही है। यदि विद्यार्थी हर समस्या का समाधान एआई

भविष्य की दिशा बनती है, तो डिजिटल

संसाधनों की समान उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती होगी। महंगे उपकरण, तेज इंटरनेट, आधुनिक कंप्यूटर और प्रशिक्षित शिक्षक हर विद्यार्थी के पास उपलब्ध नहीं हैं। यदि एक वर्ग एआई आधारित आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे और दूसरा वर्ग केवल पारंपरिक संसाधनों तक सीमित रहे, तो डिजिटल असमानता शैक्षिक असमानता को और बढ़ा सकती है। इसलिए एआई को शिक्षा में शामिल करने की नीति के साथ डिजिटल पहुंच, शिक्षक प्रशिक्षण और स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री पर भी समान जोर देना होगा। संपादकीय दृष्टिकोण भारत को एआई को शिक्षा से बाहर रखने और उसे बिना किसी नियंत्रण के स्वीकार करनेकूइन दोनों अतियों से बचना होगा। परीक्षा का भविष्य शायद न तो केवल किताब में होगा और न ही केवल चोटबॉट में। भविष्य उस मिश्रित व्यवस्था का हो सकता है जिसमें विद्यार्थी की मूलभूत समझ, तर्क क्षमता, समस्या-समाधान, रचनात्मकता, संवाद कौशल और तकनीक के जिम्मेदार उपयोग सभी का मूल्यांकन किया जाए।

## मतदाता सूची पर सवाल:चुनाव सुधार का रास्ता भरोसे से होकर क्यों गुजरता है?

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव मतदाता है और मतदाता की लोकतांत्रिक शक्ति उसकी सूची में दर्ज पहचान से शुरू होती है। इसलिए मतदाता सूची में एक भी पात्र नागरिक का नाम छूटना केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं, बल्कि उसके लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा गंभीर विषय है। यही तरह किसी अपात्र, मृत या दोहराप गए नाम का सूची में बने रहना भी चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकता है। भारत में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर आज जो राजनीतिक विवाद चल रहा है, वह इसी दोहरी चुनौती के बीच खड़ा है। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने से पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग और भाजपा इन आरोपों को खारिज करते हुए सूची को शुद्ध और अद्यतन करने की प्रक्रिया का समर्थन कर

रहे हैं। ऐसे वातावरण में सबसे जरूरी है कि राजनीतिक आरोपों और प्रशासनिक तथ्यों के बीच अंतर स्पष्ट रखा जाए। चुनावी व्यवस्था में भरोसा केवल दावों से नहीं, बल्कि पारदर्शी प्रक्रिया और जांचे जा सकने वाले आंकड़ों से बनता है। मतदाता सूची की शुद्धता क्यों जरूरी? एक लोकतांत्रिक चुनाव में मतदाता सूची आधारभूत दस्तावेज है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, वह स्थायी रूप से कहीं और स्थानांतरित हो गया है या एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है, तो ऐसे रिकॉर्ड की पहचान और सुधार आवश्यक है। लेकिन सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से हट गया तो वह चुनाव के दिन मतदान नहीं कर पाएगा। इसलिए “अपात्र नाम हटाना” और “पात्र नागरिक का अधिकार सुरक्षित रखना”क़दोनों काम साथ-साथ होने चाहिए। यहीं से SIR की बहस महत्वपूर्ण हो जाती है। पर विवाद की असली कसौटी क्या है?SIR के दौरान बड़ी संख्या में नामों के पुनरीक्षण और हटाए जाने को लेकर

विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं। एक

रिपोर्ट के अनुसार 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए जाने का मुद्दा बहस का केंद्र बना है। यह आंकड़ा अपने आप में अंतिम रूप से मताधिकार समाप्त होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रक्रिया अलग-अलग चरणों से गुजरती है और दावे-आपत्तियां तथा पुनः नामांकन की व्यवस्था मौजूद है। निर्वाचन आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि अंतिम मतदाता संख्या शेष चरणों की अंतिम प्रकाशन प्रक्रिया के बाद सामने आएगी। इसलिए सुधार आवश्यक है। लेकिन सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से हट गया तो वह चुनाव के दिन मतदान नहीं कर पाएगा। इसलिए “अपात्र नाम हटाना” और “पात्र नागरिक का अधिकार सुरक्षित रखना”क़दोनों काम साथ-साथ होने चाहिए। यहीं से SIR की बहस महत्वपूर्ण हो जाती है। पर विवाद की असली कसौटी क्या है?SIR के दौरान बड़ी संख्या में नामों के पुनरीक्षण और हटाए जाने को लेकर

उसे समय पर सूचना मिले,आवश्यक

दस्तावेज जमा करने का सरल माध्यम मिले और निर्णय के खिलाफ अपील का प्रभावी अवसर मिले। निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर की अपनी बैठक के बाद कई कदमों की जानकारी दी है। इनमें ऐसे लोगों के घर जाकर दस्तावेज लेने की व्यवस्था शामिल है जिन्हें नोटिस दिया गया है, रात में आश्रय लेने तथा पुनः नामांकन की व्यवस्था मौजूद है। निर्वाचन आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि अंतिम मतदाता संख्या शेष चरणों की अंतिम प्रकाशन प्रक्रिया के बाद सामने आएगी। इसलिए सुधार आवश्यक है। लेकिन सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से हट गया तो वह चुनाव के दिन मतदान नहीं कर पाएगा। इसलिए “अपात्र नाम हटाना” और “पात्र नागरिक का अधिकार सुरक्षित रखना”क़दोनों काम साथ-साथ होने चाहिए। यहीं से SIR की बहस महत्वपूर्ण हो जाती है। पर विवाद की असली कसौटी क्या है?SIR के दौरान बड़ी संख्या में नामों के पुनरीक्षण और हटाए जाने को लेकर

उसे समय पर सूचना मिले,आवश्यक

दस्तावेज जमा करने का सरल माध्यम मिले और निर्णय के खिलाफ अपील का प्रभावी अवसर मिले। निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर की अपनी बैठक के बाद कई कदमों की जानकारी दी है। इनमें ऐसे लोगों के घर जाकर दस्तावेज लेने की व्यवस्था शामिल है जिन्हें नोटिस दिया गया है, रात में आश्रय लेने तथा पुनः नामांकन की व्यवस्था मौजूद है। निर्वाचन आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि अंतिम मतदाता संख्या शेष चरणों की अंतिम प्रकाशन प्रक्रिया के बाद सामने आएगी। इसलिए सुधार आवश्यक है। लेकिन सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से हट गया तो वह चुनाव के दिन मतदान नहीं कर पाएगा। इसलिए “अपात्र नाम हटाना” और “पात्र नागरिक का अधिकार सुरक्षित रखना”क़दोनों काम साथ-साथ होने चाहिए। यहीं से SIR की बहस महत्वपूर्ण हो जाती है। पर विवाद की असली कसौटी क्या है?SIR के दौरान बड़ी संख्या में नामों के पुनरीक्षण और हटाए जाने को लेकर

निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है। 7 अक्टूबर को राहुल गांधी और अन्य विपक्षी संसदों के प्रदर्शन तथा हिरासत की घटनाओं ने विवाद को और राजनीतिक रूप दिया। कांग्रेस ने इसके बाद देशभर में विरोध कार्यक्रमों का आह्वान किया। लेकिन राजनीतिक विरोध और चुनावी प्रक्रिया की तथ्यात्मक जांच दो अलग-अलग विषय हैं। किसी आरोप की गंभीरता का निर्णय व्यवस्था तथा दावे-आपत्तियां दाखिल करने की अवधि को 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाना शामिल है। इन व्यवस्थाओं का वास्तविक महत्व तभी सामने आएगा जब पात्र नागरिकों तक इनकी जानकारी और पहुंच शामिल किए गए नामों के स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध कराने की है। नागरिक को केवल नोटिस नहीं, अवसर भी चाहिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति न तो कोई राजनीतिक दल है और न ही कोई सरकारी कार्यालयक़ुसबसे महत्वपूर्ण नागरिक है। यदि किसी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति है, तो उसे यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि उसका नाम क्यों प्रभावित हुआ।

सक्षम हो। ग्रामीण क्षेत्रों,बुजुर्गों,प्रवासी

श्रमिकों, गरीब परिवारों, बेघर नागरिकों और डिजिटल संसाधनों से दूर लोगों के लिए ऑफलाइन सुहायता उतनी ही आवश्यक है। चुनाव सुधार का अर्थ केवल तकनीक बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिक की पहुंच बढ़ाना भी है। क्या राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए? मतदाता सूची की शुद्धता केवल निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। राजनीतिक दल भी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और एजेंटों के माध्यम से सूची की जांच कर सकते हैं और वास्तविक त्रुटियों को आयोग के सामने रख सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में दलगत हित और नागरिक हित के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। किसी नाम का विरोध केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वह किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। इसी तरह किसी पात्र नागरिक का नाम केवल प्रशासनिक संदेह के आधार पर नहीं हटाना चाहिए, जब तक उसे उचित प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का अवसर न मिले। संपादकीय दृष्टिकोण भारत को मतदाता

सक्षम हो। ग्रामीण क्षेत्रों,बुजुर्गों,प्रवासी

श्रमिकों, गरीब परिवारों, बेघर नागरिकों और डिजिटल संसाधनों से दूर लोगों के लिए ऑफलाइन सुहायता उतनी ही आवश्यक है। चुनाव सुधार का अर्थ केवल तकनीक बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिक की पहुंच बढ़ाना भी है। क्या राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए? मतदाता सूची की शुद्धता केवल निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। राजनीतिक दल भी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और एजेंटों के माध्यम से सूची की जांच कर सकते हैं और वास्तविक त्रुटियों को आयोग के सामने रख सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में दलगत हित और नागरिक हित के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। किसी नाम का विरोध केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वह किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। इसी तरह किसी पात्र नागरिक का नाम केवल प्रशासनिक संदेह के आधार पर नहीं हटाना चाहिए, जब तक उसे उचित प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का अवसर न मिले। संपादकीय दृष्टिकोण भारत को मतदाता

सक्षम हो। ग्रामीण क्षेत्रों,बुजुर्गों,प्रवासी

श्रमिकों, गरीब परिवारों, बेघर नागरिकों और डिजिटल संसाधनों से दूर लोगों के लिए ऑफलाइन सुहायता उतनी ही आवश्यक है। चुनाव सुधार का अर्थ केवल तकनीक बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिक की पहुंच बढ़ाना भी है। क्या राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए? मतदाता सूची की शुद्धता केवल निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। राजनीतिक दल भी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और एजेंटों के माध्यम से सूची की जांच कर सकते हैं और वास्तविक त्रुटियों को आयोग के सामने रख सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में दलगत हित और नागरिक हित के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। किसी नाम का विरोध केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वह किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। इसी तरह किसी पात्र नागरिक का नाम केवल प्रशासनिक संदेह के आधार पर नहीं हटाना चाहिए, जब तक उसे उचित प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का अवसर न मिले। संपादकीय दृष्टिकोण भारत को मतदाता

सक्षम हो। ग्रामीण क्षेत्रों,बुजुर्गों,प्रवासी

श्रमिकों, गरीब परिवारों, बेघर नागरिकों और डिजिटल संसाधनों से दूर लोगों के लिए ऑफलाइन सुहायता उतनी ही आवश्यक है। चुनाव सुधार का अर्थ केवल तकनीक बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिक की पहुंच बढ़ाना भी है। क्या राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए? मतदाता सूची की शुद्धता केवल निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। राजनीतिक दल भी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और एजेंटों के माध्यम से सूची की जांच कर सकते हैं और वास्तविक त्रुटियों को आयोग के सामने रख सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में दलगत हित और नागरिक हित के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। किसी नाम का विरोध केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वह किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। इसी तरह किसी पात्र नागरिक का नाम केवल प्रशासनिक संदेह के आधार पर नहीं हटाना चाहिए, जब तक उसे उचित प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का अवसर न मिले। संपादकीय दृष्टिकोण भारत को मतदाता

सक्षम हो। ग्रामीण क्षेत्रों,बुजुर्गों,प्रवासी

श्रमिकों, गरीब परिवारों, बेघर नागरिकों और डिजिटल संसाधनों से दूर लोगों के लिए ऑफलाइन सुहायता उतनी ही आवश्यक है। चुनाव सुधार का अर्थ केवल तकनीक बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिक की पहुंच बढ़ाना भी है। क्या राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए? मतदाता सूची की शुद्धता केवल निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। राजनीतिक दल भी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और एजेंटों के माध्यम से सूची की जांच कर सकते हैं और वास्तविक त्रुटियों को आयोग के सामने रख सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में दलगत हित और नागरिक हित के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। किसी नाम का विरोध केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वह किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। इसी तरह किसी पात्र नागरिक का नाम केवल प्रशासनिक संदेह के आधार पर नहीं हटाना चाहिए, जब तक उसे उचित प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का अवसर न मिले। संपादकीय दृष्टिकोण भारत को मतदाता

सक्षम हो। ग्रामीण क्षेत्रों,बुजुर्गों,प्रवासी

श्रमिकों, गरीब परिवारों, बेघर नागरिकों और डिजिटल संसाधनों से दूर लोगों के लिए ऑफलाइन सुहायता उतनी ही आवश्यक है। चुनाव सुधार का अर्थ केवल तकनीक बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिक की पहुंच बढ़ाना भी है। क्या राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए? मतदाता सूची की शुद्धता केवल निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। राजनीतिक दल भी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और एजेंटों के माध्यम से सूची की जांच कर सकते हैं और वास्तविक त्रुटियों को आयोग के सामने रख सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में दलगत हित और नागरिक हित के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। किसी नाम का विरोध केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वह किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। इसी तरह किसी पात्र नागरिक का नाम केवल प्रशासनिक संदेह के आधार पर नहीं हटाना चाहिए, जब तक उसे उचित प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का अवसर न मिले। संपादकीय दृष्टिकोण भारत को मतदाता

सक्षम हो। ग्रामीण क्षेत्रों,बुजुर्गों,प्रवासी

श्रमिकों, गरीब परिवारों, बेघर नागरिकों और डिजिटल संसाधनों से दूर लोगों के लिए ऑफलाइन सुहायता उतनी ही आवश्यक है। चुनाव सुधार का अर्थ केवल तकनीक बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिक की पहुंच बढ़ाना भी है। क्या राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए? मतदाता सूची की शुद्धता केवल निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। राजनीतिक दल भी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और एजेंटों के माध्यम से सूची की जांच कर सकते हैं और वास्तविक त्रुटियों को आयोग के सामने रख सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में दलगत हित और नागरिक हित के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। किसी नाम का विरोध केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वह किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। इसी तरह किसी पात्र नागरिक का नाम केवल प्रशासनिक संदेह के आधार पर नहीं हटाना चाहिए, जब तक उसे उचित प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का अवसर न मिले। संपादकीय दृष्टिकोण भारत को मतदाता

सक्षम हो। ग्रामीण क्षेत्रों,बुजुर्गों,प्रवासी

श्रमिकों, गरीब परिवारों, बेघर नागरिकों और डिजिटल संसाधनों से दूर लोगों के लिए ऑफलाइन सुहायता उतनी ही आवश्यक है। चुनाव सुधार का अर्थ केवल तकनीक बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिक की पहुंच बढ़ाना भी है। क्या राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए? मतदाता सूची की शुद्धता केवल निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। राजनीतिक दल भी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और एजेंटों के माध्यम से सूची की जांच कर सकते हैं और वास्तविक त्रुटियों को आयोग के सामने रख सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में दलगत हित और नागरिक हित के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। किसी नाम का विरोध केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वह किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। इसी तरह किसी पात्र नागरिक का नाम केवल प्रशासनिक संदेह के आधार पर नहीं हटाना चाहिए, जब तक उसे उचित प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का अवसर न मिले। संपादकीय दृष्टिकोण भारत को मतदाता

सक्षम हो। ग्रामीण क्षेत्रों,बुजुर्गों,प्रवासी

श्रमिकों, गरीब परिवारों, बेघर नागरिकों और डिजिटल संसाधनों से दूर लोगों के लिए ऑफलाइन सुहायता उतनी ही आवश्यक है। चुनाव सुधार का अर्थ केवल तकनीक बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिक की पहुंच बढ़ाना भी है। क्या राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए? मतदाता सूची की शुद्धता केवल निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। राजनीतिक दल भी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और एजेंटों के माध्यम से सूची की जांच कर सकते हैं और वास्तविक त्रुटियों को आयोग के सामने रख सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में दलगत हित और नागरिक हित के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। किसी नाम का विरोध केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वह किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। इसी तरह किसी पात्र नागरिक का नाम केवल प्रशासनिक संदेह के आधार पर नहीं हटाना चाहिए, जब तक उसे उचित प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का अवसर न मिले। संपादकीय दृष्टिकोण भारत को मतदाता

सक्षम हो। ग्रामीण क्षेत्रों,बुजुर्गों,प्रवासी

श्रमिकों, गरीब परिवारों, बेघर नागरिकों और डिजिटल संसाधनों से दूर लोगों के लिए ऑफलाइन सुहायता उतनी ही आवश्यक है। चुनाव सुधार का अर्थ केवल तकनीक बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिक की पहुंच बढ़ाना भी है। क्या राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए? मतदाता सूची की शुद्धता केवल निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। राजनीतिक दल भी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और एजेंटों के माध्यम से सूची की जांच कर सकते हैं और वास्तविक त्रुटियों को आयोग के सामने रख सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में दलगत हित और नागरिक हित के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। किसी नाम का विरोध केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वह किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। इसी तरह किसी पात्र नागरिक का नाम केवल प्रशासनिक संदेह के आधार पर नहीं हटाना चाहिए, जब तक उसे उचित प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का अवसर न मिले। संपादकीय दृष्टिकोण भारत को मतदाता

सक्षम हो। ग्रामीण क्षेत्रों,बुजुर्गों,प्रवासी

श्रमिकों, गरीब परिवारों, बेघर नागरिकों और डिजिटल संसाधनों से दूर लोगों के लिए ऑफलाइन सुहायता उतनी ही आवश्यक है। चुनाव सुधार का अर्थ केवल तकनीक बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिक की पहुंच बढ़ाना भी है। क्या राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए? मतदाता सूची की शुद्धता केवल निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। राजनीतिक दल भी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और एजेंटों के माध्यम से सूची की जांच कर सकते हैं और वास्तविक त्रुटियों को आयोग के सामने रख सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में दलगत हित और नागरिक हित के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। किसी नाम का विरोध केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वह किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। इसी तरह किसी पात्र नागरिक का नाम केवल प्रशासनिक संदेह के आधार पर नहीं हटाना चाहिए, जब तक उसे उचित प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का अवसर न मिले। संपादकीय दृष्टिकोण भारत को मतदाता

सक्षम हो। ग्रामीण क्षेत्रों,बुजुर्गों,प्रवासी

श्रमिकों, गरीब परिवारों, बेघर नागरिकों और डिजिटल संसाधनों से दूर लोगों के लिए ऑफलाइन सुहायता उतनी ही आवश्यक है। चुनाव सुधार का अर्थ केवल तकनीक बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिक की पहुंच बढ़ाना भी है। क्या राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए? मतदाता सूची की शुद्ध

# दवा के कवर पर हिंदी से तमिलनाडु में सियासी संग्राम, विवाद बढ़ा तो अस्पतालों ने इस्तेमाल रोका



भारतार्थ खबर  
Bhaarataarth.com  
चेन्नई, 8 अक्टूबर 2026। तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली दवाओं के कवर पर तमिल और अंग्रेजी के साथ हिंदी में खुराक संबंधी निर्देश छपे मिलने के बाद राज्य में भाषा को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। करूर और कोयंबटूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इस्तेमाल हो रहे इन कवरों पर आपत्ति के बाद अस्पताल प्रशासन ने इनके वितरण पर तत्काल रोक लगा दी है। टीआरबी

राजा ने उठाया तीन-भाषा नीति का सवाल विवाद उस समय सामने आया जब डीएमके नेता टीआरबी राजा ने सोशल मीडिया पर करूर के सरकारी अस्पताल में इस्तेमाल किए जा रहे दवा कवर की तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में भी तीन-भाषा नीति लागू की जा रही है। उनके मुताबिक, इसी तरह के कवर कोयंबटूर में भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। तमिलनाडु में लंबे समय से तमिल और अंग्रेजी की द्विभाषी नीति को प्राथमिकता दी जाती रही है और राज्य

की राजनीति में हिंदी के इस्तेमाल का मुद्दा संवेदनशील रहा है। ऐसे में दवा के कवर पर हिंदी शब्द सामने आने से मामला महज प्रशासनिक चूक तक सीमित न रहकर राजनीतिक बहस का विषय बन गया। अस्पतालों ने क्या कहा? करूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन डॉ. एम. भारती मोहन के अनुसार, अस्पताल सामान्य तौर पर सादे भूरे कवर इस्तेमाल करता है, जिन पर फार्मसी कर्मचारी दवा लेने का समय तमिल में मुहर के जरिए अंकित करते हैं। नियमित कवर की कमी के कारण दिसंबर 2025 में की एक सहकारी प्रिंटिंग प्रेस से कवर मंगाए गए थे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इन कवरों पर हिंदी संभत अन्य निर्देश छापने के लिए अलग से आदेश नहीं दिया गया था। मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद करूर अस्पताल ने इन कवरों का इस्तेमाल बंद कर दिया। कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने भी विवादित कवर हटाकर सादे कवर

इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। दवा की खुराक और सेवन का तरीका अब मरीज की पर्ची के अनुसार कवर पर हाथ से अंकित करने की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने डीएमके के दावे पर उठाए सवाल तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री के.जी. अरुणराज ने विवाद पर डीएमके को निशाने पर लेते हुए कहा कि संबंधित कवर मौजूदा सरकार ने तैयार नहीं कराए थे। मंत्री के अनुसार, करूर में नियमित कवरों की कमी के कारण दिसंबर 2025 में चार लाख कवरों का आपात ऑर्डर दिया गया था और ये जनवरी 2026 में इस्तेमाल में आए, जब पिछली डीएमके सरकार सत्ता में थी। मंत्री ने यह भी दावा किया कि कोयंबटूर में इसी तरह के कवर करीब तीन साल से इस्तेमाल में थे और उनका डिजाइन भी पिछली सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने केवल उपलब्ध स्टॉक और अस्पतालों की आवश्यकता के आधार पर कवर मंगाए थे तथा विवाद सामने आने के

बाद दोनों अस्पतालों में उनका इस्तेमाल रोक दिया गया। भाषा नीति फिर बनी राजनीतिक मुद्दा इस घटनाक्रम ने तमिलनाडु में भाषा नीति को लेकर पुरानी राजनीतिक बहस को फिर तेज कर दिया है। एक ओर डीएमके ने हिंदी के इस्तेमाल को राज्य की स्थापित द्विभाषी नीति से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं, वहीं सरकार का कहना है कि इन कवरों का इस्तेमाल किसी नई तीन-भाषा नीति को लागू करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। फिलहाल विवादित कवरों का इस्तेमाल रोक दिया गया है। करूर में पहले की व्यवस्था बहाल करने और कोयंबटूर में तमिल-अंग्रेजी वाले नए कवर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि प्रशासनिक स्तर पर इस्तेमाल होने वाली सामग्री में भाषा संबंधी नीतियों और स्थानीय संवेदनशीलताओं का पालन किस तरह सुनिश्चित किया जाए।

## मदद के बहाने घायल के साथ अस्पताल पहुंचा , सोने की चेन लेकर फरार कुछ ही घंटों में आरोपी गिरफ्तार

भारतार्थ खबर  
Bhaarataarth.com  
अलापुझा, 8 अक्टूबर 2026। केरल के अलापुझा में सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की मदद करना एक शरख्स को इंसानियत का मौका नहीं, बल्कि कथित तौर पर चोरी का अवसर नजर आया। रविवार रात हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के दौरान आरोपी उसके साथ ऑटो रिक्शा में सवार हो गया और अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी सोने की चेन कथित तौर पर चुरा ली। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। घायल की मदद के बहाने ऑटो में सवार हुआ आरोपी पुलिस के अनुसार, हादसा रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे वंडानम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आसपास हुआ। बाइक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान आरोपी मदद करने के बहाने घायल को अस्पताल

पहुंचाने वाले ऑटो में सवार हो गया। अस्पताल पहुंचने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर घायल व्यक्ति के गले से सोने की चेन निकाल ली और वहां से फरार हो गया। कुछ समय बाद परिजनों को चेन गायब होने की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने अंबालापुझा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। सीसीटीवी ने खोली पहचान शिकायत मिलने के बाद अंबालापुझा पुलिस ने अस्पताल परिसर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस ने फुटेज और उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध की पहचान की। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को कुरावनथोडे जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्टों के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसका पीछा कर उसे पकड़ा। आरोपी पर पहले से भी मामले दर्ज पुलिस ने आरोपी की पहचान अफ्कर, निवासी पुनप्प्रा, के रूप में की है। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुछ

## आईआईएम बेंगलुरु में परीक्षा का नया प्रयोग , लिखित पेपर की जगह छात्रों ने बनाया अपना एआई चौटबॉट

भारतार्थ खबर  
Bhaarataarth.com  
बेंगलुरु, 8 अक्टूबर 2026। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच आईआईएम बेंगलुरु ने विद्यार्थियों के मूल्यांकन का एक नया तरीका अपनाकर शिक्षा जगत में चर्चा छेड़ दी है। संस्थान के जनरेटिव एआई कोर्स के जून-जुलाई 2026 सत्र में शामिल 78 छात्रों को पारंपरिक लिखित मिडटर्म परीक्षा देने के बजाय अपना खुद का एआई चौटबॉट विकसित करना पड़ा। छात्रों को इसी चौटबॉट की मदद से 15 सवालों के जवाब देने थे। इस प्रयोग का उद्देश्य केवल यह देखना नहीं था कि विद्यार्थी एआई के बारे में कितनी सैद्धांतिक जानकारी रखते हैं, बल्कि यह समझना भी था कि वे एआई तकनीक को वास्तविक और व्यावहारिक परिस्थितियों में कितनी प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। परीक्षा से ज्यादा प्रोजेक्ट जैसा रहा मूल्यांकन पारंपरिक परीक्षा में जहां छात्र निर्धारित प्रश्नपत्र के उत्तर लिखते हैं, वहीं इस मूल्यांकन में विद्यार्थियों को पहले अपना चौटबॉट तैयार करना

था। इसके बाद उन्हें उस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने थे। इस प्रक्रिया में छात्रों की तकनीकी समझ के साथ—साथ उनकी समस्या सुलझाने की क्षमता, एआई टूल के उपयोग, निर्देश देने की क्षमता और प्राप्त उत्तरों की सैद्धांतिक जानकारी है या नहीं। महत्वपूर्ण यह भी है कि वह तकनीक का उपयोग वास्तविक समस्या को हल करने में कितनी कुशलता से कर सकता है। आईआईएम बेंगलुरु का यह प्रयोग इसी बदलती शैक्षणिक जरूरत को दर्शाता है। छात्रों को एआई से उत्तर हासिल करने के बजाय अपना चौटबॉट तैयार कर उसके माध्यम से सवालों का सामना करना पड़ा। इससे यह आकलन करने का अवसर मिला कि विद्यार्थी एआई को केवल तैयार उत्तर पाने के साधन के रूप में देखते हैं या उसका उपयोग एक उपयोगी तकनीकी उपकरण के रूप में कर सकते हैं। शिक्षा में एआई के बढ़ते इस्तेमाल का संकेत आईआईएम बेंगलुरु का यह प्रयोग ऐसे समय हुआ है जब उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ परीक्षा और मूल्यांकन की पारंपरिक पद्धतियों को बदलने की चुनौती है। जनरेटिव एआई के उपलब्ध होने से केवल लिखित परीक्षाओं के जरिए विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमता का आकलन करना पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में

प्रोजेक्ट आधारित और तकनीक-केंद्रित मूल्यांकन विद्यार्थियों की व्यावहारिक दक्षताओं को परखने का एक विकल्प बन सकता है। हालांकि, ऐसी पद्धतियों में मूल्यांकन की पारदर्शिता, सभी विद्यार्थियों के लिए समान तकनीकी अवसर और एआई के उपयोग की स्पष्ट सीमाएं तय करना भी महत्वपूर्ण रहेगा। भविष्य की परीक्षाओं के लिए बन सकता है मॉडल आईआईएम बेंगलुरु का यह आकलन करने का अवसर मिला कि प्रयोग शिक्षा क्षेत्र में मूल्यांकन के बदलते स्वरूप की ओर संकेत करता है। यदि ऐसे प्रयोगों से विद्यार्थियों की वास्तविक सीख और तकनीकी दक्षता का बेहतर आकलन संभव होता है, तो आने वाले समय में अन्य उच्च शिक्षण संस्थान भी पारंपरिक परीक्षा के साथ ऐसे व्यावहारिक मूल्यांकन को अपनाने पर विचार कर सकते हैं। फिलहाल 78 छात्रों के साथ किया गया यह प्रयोग इस बात की ओर इशारा करता है कि एआई के दौर में परीक्षा का सवाल केवल यह नहीं रहेगा कि छात्र क्या जानते हैं, बल्कि यह भी होगा कि वे उपलब्ध तकनीक का इस्तेमाल करके उस ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों में कैसे लागू करते हैं।



भारतार्थ खबर  
Bhaarataarth.com  
विजयवाड़ा, 8 अक्टूबर 2026। आंध्र प्रदेश में कमजोर मानसून ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। राज्य सरकार ने दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026 के खरीफ सीजन के लिए 21 जिलों के 388 मंडलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इनमें 283 मंडलों को गंभीर और 105 मंडलों को मध्यम सूखा प्रभावित श्रेणी में रखा गया है। सरकार का यह फैसला सामान्य समय-सीमा से पहले लिया गया है। राजस्व (आपदा प्रबंधन) विभाग ने 1 अक्टूबर को आदेश जारी किया। इससे पहले 30 सितंबर को

उच्चस्तरीय सूखा समिति की बैठक में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए शुरुआती सूखा घोषणा की सिफारिश की गई थी। जून से अगस्त तक बारिश में 53.4 प्रतिशत कमी राज्य सरकार के अनुसार, 1 जून से 31 अगस्त 2026 के बीच आंध्र प्रदेश में औसतन 197.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 424.3 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। इस तरह इस अवधि में बारिश में 53.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। सरकार ने सूखा घोषित करने के फैसले में बारिश की कमी के साथ मौजूदा एल नीनों परिस्थितियों को भी महत्वपूर्ण कारण माना है। सूखे की स्थिति का असर विशेष रूप से

रायलसीमा और दक्षिणी आंध्र के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, सूखे की घोषित 388 मंडलों में से 186 मंडल रायलसीमा क्षेत्र में हैं। गंभीर सूखे की श्रेणी वाले 283 मंडलों में भी 159 मंडल इसी क्षेत्र से संबंधित हैं। राहत और कृषि सहायता का रास्ता खुलेगा सरकार ने निर्धारित समय-सीमा से पहले सूखा घोषित करने का फैसला इसलिए भी किया है ताकि प्रभावित किसानों और कृषि परिवारों के लिए राहत संबंधी उपाय तेजी से शुरू किए जा सकें। रिपोर्टों के अनुसार, सूखा घोषणा से प्रभावित परिवारों को संस्थागत ऋण और अन्य राहत उपायों तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है। यह घोषणा केंद्र सरकार के 2016 के सूखा प्रबंधन मैनुअल में निर्धारित मानकों के आधार पर की गई है। राज्य में कुल 688 मंडल हैं, जिनमें 388 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। विपक्ष ने उठाए सवाल सूखा घोषणा को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने सरकार पर सूखा घोषित करने में देरी का आरोप लगाया है। विपक्ष ने विशेष

रूप से नेल्लोर जिले को सूची से बाहर रखने पर सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि जिले के कई मंडलों में भी बारिश की स्थिति चिंताजनक रही है। ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं, सरकार का आधिकारिक सूखा आकलन 21 जिलों के 388 मंडलों पर लागू है। दीर्घकालिक समाधान पर नदी जोड़ने की बात मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सूखे की चुनौती के बीच गोदावरी और कावेरी नदी प्रणालियों को जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि गोदावरी के अतिरिक्त बाढ़ के पानी का बेहतर उपयोग दक्षिण भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों, खासकर रायलसीमा, के लिए दीर्घकालिक समाधान बन सकता है। आंध्र प्रदेश में सूखे की यह स्थिति केवल तत्काल कृषि संकट नहीं, बल्कि जल प्रबंधन, ग्रामीण रोजगार और किसानों की आय से जुड़ी व्यापक चुनौती की ओर भी संकेत करती है। आने वाले दिनों में राहत पैकेज, सिंचाई व्यवस्था और जल संरक्षण संबंधी सरकारी कदम इस संकट की गंभीरता को कम करने में महत्वपूर्ण होंगे।

# रियल एस्टेट में दिलचस्पी , किसानों की अनदेखी का आरोप विजयेंद्र ने साधा सरकार पर निशाना

भारतार्थ खबर  
Bhaarataarth.com  
बागलकोट, 8 अक्टूबर 2026। कर्नाटक में सूखे और किसानों की समस्याओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार किसानों की गंभीर समस्याओं के समाधान के बजाय रियल एस्टेट और नई परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दे रही है। बागलकोट में मीडिया से बातचीत के दौरान विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री पर किसानों की परेशानियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश की कमी के कारण लोगों और मवेशियों की स्थिति चिंताजनक है। उनके अनुसार, रोजगार के अवसर नहीं मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का अन्य स्थानों की ओर पलायन भी हो रहा है। सूखा राहत को लेकर सरकार पर सवाल विजयेंद्र ने कहा कि भाजपा की ओर से 'बेल्लारी चलो' अभियान के दौरान सूखा प्रभावित किसानों के लिए राहत की मांग उठाई गई थी। उन्होंने प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये और रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान दिया गया चाहिए। उन्होंने बागलकोट क्षेत्र से जुड़े अपर कृष्णा परियोजना

का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने परियोजना के लिए हर वर्ष 10 हजार करोड़ रुपये देने की बात कही थी, लेकिन प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने पर हजार रुपये की सहायता देने की

इनका समाधान करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में NDA की सरकार सत्ता में आएगी और भाजपा इन समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करेगी। मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ नेता सत्ता में बने

कांग्रेस के भीतर कथित स्टिंग ऑपरेशन और 'डिंग डिंग ऑपरेशन' को लेकर भी सरकार पर राजनीतिक तंज कसा। उन्होंने रे म रे शं जारकीहोली से जुड़े पुराने राजनीतिक विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता को इन घटनाक्रमों के पीछे की राजनीतिक भूमिका के बारे में जानकारी है। मुख्यमंत्री के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की इच्छा संबंधी कथित बयान पर विजयेंद्र ने कहा कि उन्हें दिन में सपने देखने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को राजनीतिक आरोप—प्रत्यारोप से आगे बढ़कर राज्य के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा मठों को लेकर दिए गए कथित बयान पर भी आपत्ति जताई और कहा कि सत्ता में आने के लिए समाज के सभी वर्गों का विश्वास हासिल करना जरूरी है। विजयेंद्र ने दावा किया कि मतदाताओं का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। हालांकि, विजयेंद्र के इन आरोपों और राजनीतिक दावों पर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार या कांग्रेस की ओर से इस बयान के संदर्भ में कोई प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया इस समाचार सामग्री में उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन दावों को विजयेंद्र के राजनीतिक आरोप और बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।



भारतार्थ खबर  
Bhaarataarth.com  
बेंगलुरु, 8 अक्टूबर 2026। मारुति नगर, चंद्रा लेआउट में गजानन गेलेयारा बलेगा मारुति

नगर चंद्रा लेआउट संगठन की ओर से गणेश उत्सव श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आयोजन में श्रद्धालुओं ने भगवान गणपति के दर्शन कर सुख-समृद्धि

और मंगलमय जीवन की कामना की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महेंद्र मुणोत ने भगवान गणपति के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर संगठन की ओर से सामाजिक सरोकार को बढ़ावा देते हुए रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के दौरान महेंद्र मुणोत ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि रक्तदान जीवनदान है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा दान किया गया एक यूनिट रक्त जरूरत के समय कई लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने लोगों से नियमित रूप से, चिकित्सकीय पात्रता के अनुसार, रक्तदान जैसे मानवीय कार्यों में सहभागी बनने का आह्वान किया। शिविर में एकत्रित रक्त का संग्रहण लायंस रुधिर संस्थान, विजयनगर द्वारा किया गया। आयोजन के दौरान सामाजिक सेवा में योगदान देने वाले रक्तदाताओं के उत्साहवर्धन के साथ सेवा भावना को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर आयोजकों की ओर से महेंद्र मुणोत का सम्मान किया गया। गणेश उत्सव के धार्मिक आयोजन के साथ रक्तदान शिविर के माध्यम से सामाजिक सेवा का संदेश भी दिया गया, जिससे श्रद्धा और जनसेवा का समन्वय देखने को मिला।

## गुजरात से 3 लाख से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर करने का शुभेंदु अधिकारी का दावा



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com वडनगर, 8 अक्टूबर 2026। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुजरात के वडनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि गुजरात की भाजपा सरकार ने राज्य से तीन लाख से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला है। उन्होंने पश्चिम बंगाल

में वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लंबे शासन पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इससे राज्य की स्थिति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हुई। अधिकारी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर मेहसाणा जिले के वडनगर में आयोजित ‘वाराणसी से वडनगर सेवा यात्रा’ के समापन समारोह को संबोधित करते हुए यह दावा किया।

## बेंगलुरु में अमेजन कार्यालय के बाहर फुटपाथ पर आरएमयू में जोरदार धमाका , राहगीर झुलसा

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 8 अक्टूबर 2026। बेंगलुरु के बागलूर मेन रोड पर अमेजन कार्यालय के बाहर बुधवार सुबह फुटपाथ पर लगे बिजली के रिंग मेन यूनिट (आरएमयू) में अचानक जोरदार धमाका होने से अफरा–तफरी मच गई। घटना में फुटपाथ से गुजर रहा एक राहगीर झुलस गया। धमाके का पूरा घटनाक्रम एक कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद सड़क किनारे लगे विद्युत उपकरणों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अचानक हुआ विस्फोट, राहगीर के हाथ झुलसे पुलिस के अनुसार, घटना बुधवार सुबह करीब 9:40 बजे जेलहंका थाना क्षेत्र में बागलूर क्रॉस के पास हुई। फुटपाथ से गुजर रहे मोहम्मद अफरोज आरएमयू के नजदीक थे, तभी तेज आवाज के साथ उसमें विस्फोट हो गया। धमाके के बाद अफरोज के हाथों पर चलने की चोटें आईं और वह सड़क पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उनकी मदद की और उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। पुलिस ने घटना की जानकारी जुटानी शुरु कर

### राजस्थान में मतदाता बनने की बड़ी रफ्तार, सात

### दिन में 57 हजार से अधिक फॉर्म–6 आवेदन

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com जयपुर, 8 अक्टूबर 2026। राजस्थान में मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए शुरु किए गए विशेष अभियान को शुरुआती दिनों में उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली है। अभियान के पहले सात दिनों में प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए 57 हजार से अधिक फॉर्म–6 आवेदन प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार, इस विशेष अभियान का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची में शामिल होने से रह गए पात्र नागरिकों के साथ–साथ 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करना है। निर्वाचन विभाग ने पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अभियान का लाभ उठाने की अपील की है। युवाओं को मतदाता बनने के लिए किया जा रहा जागरूक निर्वाचन विभाग की ओर से नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता गतिविधियां एवं विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मतदाता साक्षरता क्लबों के माध्यम से युवाओं को मतदात के अधिकार, पंजीकरण प्रक्रिया और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की जानकारी दी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारियों और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को अभियान की निगरानी तथा प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। निर्वाचन विभाग के मुख्यालय स्तर पर भी अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। फॉर्म–6 से नए मतदाता कर संकेत हैं आवेदन भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदाता सूची में पहली बार नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म–6 का उपयोग किया जाता है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म–6 उपलब्ध है। पात्र नागरिक ऑनलाइन माध्यम से मतदाता सेवा पोर्टल अथवा ईसीआईनेट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से भी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। भारत निर्वाचन आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए फॉर्म–6 के माध्यम से नए मतदाता पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। समावेशी मतदाता सूची पर जोर विशेष अभियान का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे। खासतौर पर हाल में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं तथा ऐसे नागरिकों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। मतदाता सूची का अद्यतन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ–साथ निर्वाचन विभाग का प्रयास है कि सूची अधिक समावेशी और अद्यतन रहे। राजस्थान में सात दिनों के भीतर 57 हजार से अधिक फॉर्म–6 आवेदन मिलना इस अभियान के प्रति नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का संकेत माना जा रहा है।

**Printed Published & Owner by Dhanna Ram Choudhary And Printed at MNS Printers Pvt. Ltd., No.345/4, Bhattarahalli, Old Madras Road, Bengaluru Karnataka-560049. And Published at "Maruthi“Plaza”“, No. 10/1, 1st Cross Road, 3rd Floor , Oil Mill Road, Arvind Nagar , Maruthi Seva Nagar Post, Kammanahalli, Bengaluru Urban, Karnataka -560033, Editor Dhanna Ram Choudhary , For Editorial 91641 17755, 93412 59043**

**Advertisement 88676 89130 , PRGI NO.: KINH/26/A5540 E-Mail: news@bhaarataarth.com, Website: bhaarataarth.com, Established: 2026**

उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संधवी के नेतृत्व में राज्य से तीन लाख से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया गया है। बंगाल की राजनीति पर भी साधा निशाना शुभेंदु अधिकारी ने अपने संबोधन में पश्चिम बंगाल की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वामपंथी दलों और टीएमसी के करीब 50 वर्षों के शासन ने राज्य को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन सरकारों के कार्यकाल में ऐसी परिस्थितियां बनीं, जिनसे देश की सुरक्षा के सामने चुनौतियां पैदा हुईं। उन्होंने दावा किया कि भारत–बांग्लादेश सीमा से संबंधित व्यवस्थाओं और कथित अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर पिछली सरकारों का रवैया गंभीर नहीं था। हालांकि, ये आरोप राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं और इनके समर्थन में प्रस्तुत तीन लाख से अधिक लोगों के निष्कासन

के आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं की गई है। गुजरात में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई गुजरात में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान को लेकर वर्ष 2026 में पुलिस ने अभियान भी चलाया था। जून में गुजरात पुलिस के ‘ऑपरेशन डेल्टा हंट’ के दौरान अहमदाबाद, राजकोट, सूрат, वडोदरा और मोरबी सहित कई शहरों में कार्रवाई की गई थी। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संधवी के अनुसार, अभियान में 362 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई थी। यह आंकड़ा शुभेंदु अधिकारी द्वारा बताए गए तीन लाख से अधिक के आंकड़े से अलग है। इसलिए दोनों आंकड़ों को एक–दूसरे का पर्याय मानना उचित नहीं होगा। तीन लाख से अधिक लोगों को गुजरात से बाहर किए जाने के दावे की पुष्टि के लिए आधिकारिक विस्तृत आंकड़ों की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा

### 17 हजार फीट की ऊंचाई पर इंडिगो विमान पर गिरी

### आकाशीय बिजली, नोज क्षतिग्रस्त सभी यात्री सुरक्षित

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

लखनऊ, 8 अक्टूबर 2026। पटना से लखनऊ आ रही इंडिगो की एक उड़ान बुधवार को करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई पर खराब मौसम के बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। घटना के बाद विमान के अगले हिस्से यानी ‘नोज’ को नुकसान पहुंचा। हालांकि, पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सुरक्षित उतार लिया। विमान में सवार 104 यात्रियों और छह कू सदस्यों समेत सभी 110 लोग सुरक्षित रहे। जानकारी के अनुसार, इंडिगो की उड़ान पटना से लखनऊ के लिए रवाना हुई थी। लखनऊ पहुंचने से पहले विमान करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई पर था, तभी खराब मौसम के दौरान विमान के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। सामने आई तस्वीर में विमान की नोज क्षतिग्रस्त दिखाई

दे रही है। सुरक्षित लैंडिंग से टला बड़ा खतरा आकाशीय बिजली की चपेट में आने के बाद विमान को सुरक्षित रूप से लखनऊ लाया गया।



रिपोर्टों के मुताबिक, विमान निर्धारित समय से करीब आठ मिनट पहले लखनऊ में उतर गया। लैंडिंग के बाद हुए नुकसान के वास्तविक कारण की पुष्टि तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। घटना के बावजूद पायलटों ने स्थिति को नियंत्रित रखा और विमान को सुरक्षित गंतय तक पहुंचाया।

# मिथुन चक्रवर्ती को बंगाल सरकार में बड़ी जिम्मेदारी, कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ बने सांस्कृतिक सलाहकार



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

कोलकाता, 8 अक्टूबर 2026। दिग्गज अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मिथुन चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी

सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार ने उन्हें सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग में सलाहकार नियुक्त किया है। खास बात यह है कि इस पद के लिए उन्हें कैबिनेट मंत्री के दर्जे से नवाजा

गया है। नियुक्ति तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। सरकारी अधिसूचना से नियुक्ति की पुष्टि मिथुन चक्रवर्ती की नियुक्ति को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल के आदेश से मिथुन चक्रवर्ती को सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग में पश्चिम बंगाल सरकार का सलाहकार नियुक्त किया गया है, जिसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होगा। सरकारी आदेश में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से लागू करने तथा अगले आदेश तक जारी रखने की बात कही गई है। इससे यह स्पष्ट है कि मिथुन चक्रवर्ती को राज्य सरकार में एक औपचारिक प्रशासनिक भूमिका मिली है, हालांकि उनके सलाहकार के रूप में कार्यक्षेत्र और विशिष्ट जिम्मेदारियों का विस्तृत स्वरूप आगे स्पष्ट किया जाना है। शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही किया

था ऐलान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मिथुन चक्रवर्ती को सांस्कृतिक सलाहकार बनाए जाने की घोषणा पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान कर दी थी। यह घोषणा बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता उत्तम कुमार की जन्मशती से जुड़े कार्यक्रम के दौरान हुई थी। सरकार की ओर से बंगाल की फिल्म और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने तथा राज्य को प्रमुख सांस्कृतिक एवं सिनेमाई केंद्र के रूप में मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती का बंगाली और हिंदी सिनेमा में लंबा और प्रभावशाली करियर रहा है। ऐसे में संस्कृति और फिल्म क्षेत्र से जुड़े मामलों में उनके अनुभव को सरकार के लिए उपयोगी माना जा रहा है। भाजपा के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं मिथुन मिथुन चक्रवर्ती लंबे समय से पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रमुख सेलिब्रिटी चेहरों और प्रचारकों में रहे हैं। उन्होंने 2021 में भाजपा का दामन थामा था और 2026 के

### नाना पाटेकर का 75 वर्ष की उम्र में निधन, भारतीय सिनेमा ने खोया दमदार कलाकार

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता अशोक कुमार सिंह मुंबई, 8 अक्टूबर 2026। हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता एवं फिल्मकार नाना पाटेकर का गुरुवार को 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गोवा स्थित अपने आवास पर अस्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अस्पताल के अनुसार उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। नाना पाटेकर के निधन की खबर सामने आते ही भारतीय फिल्म जगत और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने भी निधन की पुष्टि की। रिपोर्टों के अनुसार, नाना पाटेकर को गोवा स्थित उनके आवास पर अचेत अवस्था में पाए जाने के बाद मणिपाल अस्पताल ले जाया गया था। चिकित्सकों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें सीपीआर देकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। करीब पांच दशक का यादगार फिल्मी सफर नाना पाटेकर का वास्तविक नाम विश्वनाथ पाटेकर था। महाराष्ट्र में जन्मे नाना पाटेकर ने मराठी रंगमंच से अपने अभिनय सफर की शुरुआत की और बाद में हिंदी तथा मराठी सिनेमा में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनका फिल्मी करियर करीब पांच दशकों तक चला। ‘गमन’ से फिल्मी सफर शुरू करने के बाद उन्होंने ‘परिदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘सलाम बॉम्बे!’ और ‘वेलकम’ सहित कई फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं। गंभीर और सामाजिक विषयों से लेकर हास्य एवं व्यावसायिक सिनेमा तक उन्होंने अलग–अलग तरह के किरदारों को अपनी विशिष्ट संवाद अदायगी और प्रभावशाली अभिनय से पहचान दी। उनकी अभिनय शैली में तीव्रता, स्पष्ट संवाद और मजबूत स्क्रीन उपस्थिति प्रमुख विशेषताएं मानी जाती थीं। ‘क्रांतिवीर’ सहित विभिन्न फिल्मों में उनके अभिनय को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। उन्हें तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और वर्ष 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिल्म जगत में शोक नाना पाटेकर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित फिल्म जगत की कई प्रमुख हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने उनके अभिनय की विशिष्टता, रचनात्मकता और प्रभावशाली उपस्थिति को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। अभिनेता अश्वय कुमार समेत कई कलाकारों ने भी उनके साथ काम के अनुभवों और उनकी अभिनय प्रतिभा को स्मरण किया। नाना पाटेकर का निधन हिंदी और मराठी सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति माना जा रहा है। रंगमंच से लेकर बड़े पर्दे तक उन्होंने अपनी अलग अभिनय पहचान बनाई और कई ऐसे किरदार छोड़े, जिन्हें दर्शक लंबे समय तक याद करते रहेंगे।



# आत्म–विशुद्धि से कर्म बंध तक वीरसागर जी महाराज ने समझाया धर्म का वास्तविक मार्ग

### भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 8 अक्टूबर 2026। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 वीरसागर जी महाराज ने मंगल प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित धर्मसभा में जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत, आत्म–विशुद्धि, संयम और नैतिक आचरण पर सारगर्भित मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि आत्मकल्याण का मार्ग केवल बाहरी धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, वचन और काय की शुद्धता तथा निर्मल भावों से होकर गुजरता है। देश–विदेश में डिजिटल माध्यमों से प्रसारित मंगल देशना में मुनिश्री ने कर्म सिद्धांत को दैनिक जीवन की गतिविधियों से जोड़ते हुए कहा कि जीव मन, वचन और काय के माध्यम से निरंतर कर्मों के आस्रव और बंध का कारण बनता है। ऐसे में व्यक्ति के लिए अपने विचारों, भावनाओं और कर्म के प्रति सजग रहना आवश्यक है। भावों की दिशा तय करती है कर्म बंध की दिशा मुनिश्री ने जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताया कि जीव के श्रुम–अश्रुम भाव उसके कर्म बंध की दिशा को प्रभावित करते हैं। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया और लोभ जैसी प्रवृत्तियां अशुभ कर्म बंध का कारण बनती हैं, जबकि शुभ भाव पुण्य उन्होंने कहा कि मनुष्य कई बार जीवन में आने वाली परिस्थितियों के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार मानता है, जबकि जैन दर्शन

व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और अपने भावों का निरीक्षण करने की प्रेरणा देता है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर मौजूद कमियों को पहचानकर भावों को शुद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। मुनिश्री ने कर्मों के व्यापक प्रभाव की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि जैन दर्शन में कर्मों का प्रभाव वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं माना गया है। जीव के कर्म उसकी आगामी पर्यायों को भी



प्रभावित करते हैं। इसलिए वर्तमान जीवन में किए जाने वाले विचार, निर्णय और आचरण का विशेष महत्व है। कुविचारों पर नियंत्रण से शुरु होती है आत्म–विशुद्धि धर्मसभा में मुनिश्री ने कुविचारों और चारित्रिक बंध की दिशा मुनिश्री ने जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत को व्याख्या करते हुए बताया कि जीव के श्रुम–अश्रुम भाव उसके कर्म बंध की दिशा को प्रभावित करते हैं। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया और लोभ जैसी प्रवृत्तियां अशुभ कर्म बंध का कारण बनती हैं, जबकि शुभ भाव पुण्य उन्होंने कहा कि मनुष्य कई बार जीवन में आने वाली परिस्थितियों के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार मानता है, जबकि जैन दर्शन

करनी चाहिए। संयम, ब्रह्मचर्य की भावना और इंद्रिय–निग्रह केवल साधु जीवन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि गृहस्थ जीवन में भी इन मूल्यों की उपयोगिता है। इनका उद्देश्य व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों का नियंत्रक बनाना है। मन, वचन और व्यवहार में हो एकरूपता आर्जव धर्म की चर्चा करते हुए मुनिश्री ने कहा कि व्यक्ति के मन, वचन और काय में एकरूपता होनी चाहिए। मन में कुछ अथवा दूसरों को धोखा देकर प्राप्त सफलता को वास्तविक आत्मिक उन्नति नहीं माना जा सकता। जीवन में सत्य, सरलता और ईमानदारी को व्यवहार का आधार बनाने की आवश्यकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में समता ही साधना मुनिश्री ने कहा कि जीवन की परिस्थितियां हमेशा मनुष्य की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होतीं। अनुकूल परिस्थितियों में प्रसन्न रहना आसान है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन को संतुलित और शांत बनाए रखना आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण पक्ष है। उन्होंने कहा कि किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या अथवा कुभाव उत्पन्न होने पर तत्काल प्रतिक्रिया देने के बजाय व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए। भावों की शुद्धि और समता का अभ्यास मानसिक अशांति को कम करने के साथ कर्म बंध को रोकने की दिशा में भी

सहायक हो सकता है। स्वाध्याय और सत्संग से निर्मल होते हैं भाव मुनिश्री ने देव–शास्त्र–गुरु के प्रति श्रद्धा, जिनवाणी का श्रवण, स्वाध्याय और सत्संग को आत्मिक उन्नति के महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शरीर के स्वास्थ्य के लिए उचित आहार आवश्यक है, उसी प्रकार मन और आत्मिक जीवन के लिए श्रेष्ठ विचारों तथा जिनवाणी के चिंतन का आवश्यकता होती है। उन्होंने श्रद्धालुओं को प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण के लिए समय निकालने की प्रेरणा दी। दिनभर के कार्यों, वाणी और मन में उत्पन्न भावों की समीक्षा व्यक्ति को अपनी कमियों को पहचानने और उनमें सुधार करने का अवसर देती है। धर्म का प्रभाव आचरण में दिखाई दे मुनिश्री ने श्रद्धालुओं को सावधान रहने का संदेश देते हुए छल–कपट से बचने, कुविचारों को बढ़ने नहीं देने, विषयासक्ति पर नियंत्रण रखने, किसी के प्रति दुर्भावना से बचने और अपने आचरण को शुद्ध रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। धर्म की सार्थकता तभी है, जब उसके सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार, विचार और चरित्र में दिखाई दें। वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन बाहरी प्रदर्शन से नहीं, बल्कि अंतर्मन में होने वाले परिवर्तन से प्राप्त होता है। श्रद्धालुओं में दिखा आध्यात्मिक उत्साह मंगल देशना के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने धर्मसभा में उपस्थित होकर प्रवचन का लाभ लिया।